14 अगस्त, 2014

भारत-नेपाल संबंध: एक नई शुरूआत

डॉ. अमित कुमार *

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की 4 अगस्त, 2014 को सम्पन्न हुई दो दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान भारत-नेपाल संबंधों में एक नई शुरुआत हुई है। प्रधान मंत्री ने नेपाल के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और संबंधों को एक नई ऊँचाई तक ले जाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का वायदा किया। इसके अलावा, नेपाल की संप्रभुता और नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के आश्वासन पर बार-बार जोर देने के साथ ही उन्होंने नेपाल के लोगों के दिलो-दिमाग को जीतने और एक इसके अलावा, नेपाल की संप्रभुता और नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के आश्वासन पर बार-बार जोर देने के साथ ही उन्होंने नेपाल के लोगों के दिलो-दिमाग को जीतने और एक आधिपत्यकारी शक्ति के रूप में भारत की छवि को कुछ हद तक दूर करने का सफल प्रयास किया।

प्रधानमंत्री ने 1950 के शांति एवं मैत्री संधि को संशोधित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा "भारत इस संधि की समीक्षा करने के लिए नेपाल सरकार के सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने के लिए तैयार है।" नेपाली आलोचक संधि को "पक्षपातपूर्ण" मानते है और विगत में नेपाल ने इस संधि में संशोधन करने के मुद्दे को उठाया है और द्विपक्षीय वार्ताओं में इसे एक प्रमुख कार्यसूची/एजेंडा के रूप में रखने की कोशिश की है लेकिन उसने इसके लिए कोई सुझाव नहीं दिए। वर्ष 1950 की मैत्री संधि के प्रति नेपाल का अविश्वास/संदेह मुख्य रूप से इस तर्क पर आधरित है कि यह संधि "संप्रभु विदेश एवं सुरक्षा नीति" पर अमल करने की इसकी क्षमता को कमजोर करती है। इस 'संधि' में कोई संशोधन अथवा संयोजन दोनों देशों के हितों को साधेगा। भारत को भारत-विरोधी धारणा को निष्प्रभावी बनाने का अवसर प्राप्त होगा जबकी नेपाल को चिरस्थायी संदेहों/उलझनों को दूर करने और भारत के साथ अपने संबंधों पर भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने का अवसर प्राप्त होगा। अब यह काठमांडू पर निर्भर है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव पर विचार करे और बदलाव के लिए बातचीत प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करे।

प्रधान मंत्री मोदी ने नेपाली संविधान निर्माताओं और राजनीतिक नेताओं के प्रति समर्थन व्यक्त किया और नेपाली नेतृत्व और जनता को "अगले वर्ष की शुरुआत तक नया संविधान प्रख्यापित करने की भारत सरकार तथा जनता की ओर से शुभकामनाएं दीं।" नेपाल वर्ष 2012 में किसी नए संविधान का प्रारूप तैयार किए बिना संविधान सभा भंग किये जाने के बाद से संवैधानिक संकट झेल रहा है। प्रधान मंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि संविधान सभा संघीय एवं लोकतांत्रिक राजनीतिक अवसंरचना का समर्थन करने तथा देश में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करेगा। नेपाल के राजनीतिक नेताओं को आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा "हम संविधान को समय पर लाने के लिए सभी आवश्यक सहायता देने को तैयार हैं।" नेपाल के संविधान सभा में दिए उनके भाषण को "राजनीतिक विचारधारा" से ऊपर उठकर अनेक नेपाली नेताओं द्वारा सराहा गया था। यह दिलचस्प है कि पुष्प कुमार दहाल अथवा प्रचंड, जो भारत के कट्टर आलोचक रहे हैं, ने मार्मिक, प्रेरक और उत्साहवर्धक भाषण के लिये प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की। यूनाइट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल - माओवादी (यूसीपीएन-एम) के अध्यक्ष प्रचंड ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद विश्वास व्यक्त किया "भारत नेपाल संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हो गया है।"

इस दौरे के अंत में जारी एक संयुक्त वक्तव्य में आर्थिक व व्यापार सहयोग बढ़ाने के तौर-तरीकों का पता लगाने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजमार्ग, सूचना प्रौद्योगिकी और बिजली के लिए संचरण लाइनों के विकास के माध्यम से नेपाल की सहायता करने के लिए एचआईटी की संकल्पना/अवधारणा को रेखांकित किया। भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों की खस्ता हालत, सीमावर्ती राज्यों में बिजली की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर और नेपाल तथा भारतीय क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में संचार नेटवर्क की खराब और दयनीय हालत में सुधार लाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि सड़कों, सूचना के तौर-तरीकों और बिजली की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर सुधार लाया जा सके।

यह प्रत्याशित था कि विद्युत व्यापार करार (पीटीए) पर प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किया जाना था पर दोनों सरकारें इस दौरे से पहले विद्युत व्यापार पर किसी सहमति पर नहीं पहुँच सकीं। जल संसाधनों पर भारत के "संभावित" एकाधिकार के संबंध में नेपाल की आशंका परस्पर स्वीकार्य करार पर पहुँचने में विलम्ब का कारण बन रही है। बाधाओं के बावजूद, दोनों पक्ष आशावादी हैं और वे आने वाले महीनों में इस सौदे को पक्का करने के लिए आवश्यक तैयारियां कर लेंगे। नेपाल के पास लगभग 83,000 मेगावाट (एमडब्ल्यू) संभावित जलविद्युत क्षमता है, जिसमें से लगभग 40,000 मेगावाट तकनीकी रूप से और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है, जो महत्वपूर्ण निर्यात क्षमता प्रस्तुत करता है, और स्पष्ट रूप से यह विदेशी मुद्रा की भारी धनराशि प्राप्त करने का शानदार अवसर है। ठप पड़ी परियोजनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने आग्रह किया कि महाकाली नदी पर 5600 मे. वा. की पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना का प्रारंभ शीघ्र किया जाना चाहिए। इस यात्रा के अंत में जारी एक संयुक्त वक्तव्य के अनुसार "दोनों पक्षों ने अन्य तीन परियोजना विकास करारों (पीडीए), नामत: अरुण III, अपर मारस्यांग्डी और तमाकोसी III को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस आकार की परियोजनाओं का विकास नेपाल की अपार जलविद्युत क्षमता के विकास के लिए प्रमुख उत्प्रेरक होगा।"

प्रधानमंत्री की यात्रा पर संयुक्त वक्तव्य में "दोनों देशों ने एक दूसरे के विरूद्ध अपने क्षेत्र/भूभाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने की अपनी-अपनी सरकारों की प्रतिबद्धता की पुन:पुष्टि की।" बार-बार के आश्वासनों के बावजूद, दोनों पक्ष अंतर-राष्ट्रीय अपराधियों द्वारा खुली सीमा का दुरुपयोग करने में कमी लाने में सफल नहीं हो पाए हैं। अंतर-राष्ट्रीय अपराध को कम करने के लिए, दोनों देशों को एक प्रभावी संयुक्त सीमा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। सतत निगरानी, संयुक्त गश्त और अंतर-राष्ट्रीय अपराधियों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य बल का गठन करके सीमा के आस-पास की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। सीमा के आर-पार व्यापार और पारगमन में सुधार लाने के उद्देश्य से, दोनों देश सभी पांच सहमत सीमा बिन्दुओं और चार समेकित चेक पोस्टों (आईसीपीज़) के आस-पास सीमा रेल का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। यात्रा के अंत में जारी एक संयुक्त वक्तव्य के अनुसार "दोनों प्रधान मंत्रियों ने सीमा के आर-पार रेल निर्माण के कार्य की गति तेज करने के लिए सक्षम अधिकारियों को निदेश दिया।" यह एक स्वागत योग्य कदम है, जिसकी सराहना करनी होगी। भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों तथा रेलमार्गों की उन्नत तंत्र व्यवस्था नेपाल के साथ भारत के वृहत्तर आर्थिक संपर्क के दृष्टिकोण की पूरक होंगी।

इस यात्रा ने भारत-नेपाल रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरूआत की है।"संघीय एवं लोकतांत्रिक गणराज्य" के विचार की पुष्टि करके प्रधान मंत्री मोदी ने नेपाल के इस डर को दूर कर दिया कि भारत की नई सरकार कहीं राजशाही की बहाली के लिए काम न करने लगे। नेपाल की संसद में उनके प्रभावशाली भाषण ने नेपाली लोगों के दिलो-दिमाग को जीत लिया। दोनों देशों ने नई विकासात्मक परियोजनाओं का समर्थन किया, सीमा पर शांति और सुरक्षा की स्थिति में सुधार लाने की अपनी इच्छा दिखाई, सीमा अवसंरचना में सुधार करने का वादा किया, और अनेक परियोजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की। वास्तव में, भारत-नेपाल संबंधों में एक गति पैदा की जा चुकी है और बेहतर अनुवर्ती कार्रवाई तथा कार्यान्वयन से इसे जारी रखना होगा।

* डॉ. अमित कुमार, भारतीय विश्व कार्य परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता।